VISION IAS

17 SEP 2019

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1248)

Name of Candidate	Ravi Kumar Sihag		
Medium Eng./Hindi	Hindi	**Registration Number**	168117
Center	MN	**Date**	17/09/19

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. Explain the significance of Credit Rating Agencies (CRAs) in India and highlight the issues in their working. **(150 words) 10**

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) का महत्व स्पष्ट कीजिए और इनकी कार्यप्रणाली से संबद्ध मुद्दों को रेखांकित कीजिए।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से तात्पर्य उन संस्थाओं से है जो किसी उद्यम, फर्म एवं कंपनी की विभिन्न परिस्थितियों, जैसे - परिसंपत्ति - देयता संतुलन, कुल तरलता स्थिति, ऋणों की मात्रा का अनुमान कर उन्हें निश्चित अंक प्रदान करती है, जिससे उन कंपनियों को ऋण आदि लेने में मदद मिलती है। उदा० क्रिसिल, मूडीज आदि।

महत्व

① कंपनियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी देना

② निवेशकों की विश्वास बहाली करना।

③ ऋण के संभावित जोखिमों का आकलन करना।

④ भारत के वित्तीय बाजार के सुदृढ़ीकरण में सहायता करना।

⑤ विदेशी निवेश को बढ़ाना।

⑥ कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB), मसाला बॉण्ड जैसे नवाचारी

कदमों को बढ़ाने में मदद करना।

प्रमुख मुद्दे

① 'भुगतानकर्त्ता जारीकर्त्ता मॉडल' के कारण 'हितों का संघर्ष।'

② प्रतिस्पर्द्धा की कमी (कम एजेंसियों का एकाधिकार।

③ 'रेटिंग शॉपिंग' का मुद्दा।

④ एजेंसियों के पास प्रभावी मूल्यांकन तंत्र की कमी।

⑤ 'अवसंरचना' व 'मानव संसाधन' का अभाव।

उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिये उचित विनियमन, एजेंसियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, 'सब्सक्राइबर पे' जैसे उपागमों का विस्तार कर हल किया जा सकता है

2. What are the issues that have limited the success of Special Economic Zones (SEZs) in India? Mention some steps that can be taken to address them. **(150 words) 10**

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) की सफलता को सीमित करने वाले मुद्दें क्या हैं? इन्हें दूर करने के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ कदमों का उल्लेख कीजिए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र से तात्पर्य देश के भीतर बाहरी माने ~~व~~ जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र से है जो व्यापारिक संचालनों, शुल्कों व प्रशुल्कों के संबंध में विदेशी माने जाते हैं।

चीन की भाँति भारत में सेज (SEZ) की सीमित सफलता के निम्न कारण है -

① अप्रयुक्त भूमि व भूमि उपयोग विपथन करना (25000 हेक्टर से अधिक भूमि अनुपयुक्त)

② 'सेज' का घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) से व्यवहार में समस्या जैसे -
- 'जॉब वर्क' की अनुमति नहीं।
- 'मुक्त व्यापार व्यवस्था' नहीं।
- व्यापार करने पर शुल्कों का भुगतान।

③ कर संरचना से संबंधित मुद्दे जैसे MAT आदि कर।

④ निर्यात प्रोत्साहन हेतु निर्माण किन्तु बंदरगाहों से अत्यन्त दूरी - उदा॰ जयपुर में महिन्द्रा सेज़ |

⑤ अन्य - अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे |

कदम - 'बाबा कल्याणी समिति' के अनुसार -

① सेज के बजाय तीन 'ई' - आर्थिक व रोजगार अन्तःक्षेत्र का निर्माण करना |
- मुख्य फोकस आर्थिक विकास व रोजगार |

② मंजूरी व परिचालनगत स्वतंत्रता व प्रोत्साहन
- सिंगल विंडो सिस्टम |
- कर प्रोत्साहन | (सनसेट क्लॉज के साथ)

③ सूचना प्रौद्यो॰ (ITES) की सफलता को अन्य क्षेत्रों में दोहराना |

④ चीनी मॉडल से सीख लेना - बड़ा आकार, बड़ा घरेलू बाजार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदि |

इस प्रकार उपर्युक्त उपायों के साथ व्यापक मंत्रालयी समन्वय के साथ व्यापक प्रोत्साहनों के साथ आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना में वृद्धि करना स्वागतयोग्य कदम होगा |

3. The opportunities for start-ups in India are immense, but so are the challenges. Discuss. **(150 words) 10**

भारत में स्टार्ट-अप्स के लिए असीमित अवसर हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही हैं। चर्चा कीजिए।

स्टार्ट-अप्स से तात्पर्य उन नवाचारी उद्यमों से है जो नवीन व ~~अन्य~~ अनन्य विषय में व्यवसाय का शुभारंभ करते हैं।

भारत में अवसर

① बड़ा भौगोलिक आकार व विशाल जनसंख्या
- बड़ा बाजार।

② सरकारी प्रोत्साहन — स्टार्ट-अप नीति।
— स्टार्ट-अप इंडिया पहल।
- कर प्रोत्साहन।
- पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहन।
- श्रम कानून अनुपालन में सहूलियत।

③ पारिस्थितिकी तंत्र की मौजूदगी
- IT क्षेत्र के विशेषज्ञों की बहुलता।
- बैंगलोर जैसे IT शहरों का होना।
- सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में उन्नत पक्ष।

④ भारत में इंजीनियर्स व स्टेम [STEM] पेशेवरों का विद्यमान होना।

चुनौतियां

① 'क्लस्टर एप्रोच' का अभाव

- फॉरवार्ड - बैकवार्ड लिंकेज का अभाव।

② अवसंरचना स्टार्ट-अप में कम निवेश।

- केवल मोबाइल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश उदा०- ओला, उबर, जोमैटो आदि।
- कृषि जैसे क्षेत्र उपेक्षित।

③ 'कुशल श्रम' का अभाव। (निचले स्तरों पर)

④ आर्थिक समीक्षा 2016-17 में 'स्टार्ट-अप बबल्स' की समस्या का विवेचन किया जिसमें और लाभकारी स्टार्ट-अप्स की बढ़ती संख्या की समस्या का ज़िक्र किया गया है।

⑤ निर्यात प्रोत्साहन, अवसंरचना, विद्युत संबंधी मुद्दे।

अतः स्टार्ट अप इंडिया पहल में आवश्यक संशोधन कर सभी क्षेत्रों में इनके नियोजन को प्रोत्साहन देते हुए अवसंरचना विकास करना समय की मांग है।

4. The term 'Circular Economy' is often seen in news. What are the principles that it is based on? Bring out its relevance for India. **(150 words) 10**

'चक्रीय अर्थव्यवस्था' (सर्कुलर इकॉनमी) पद प्रायः सुर्खियों में रहता है। वे कौन-से सिद्धांत हैं जिन पर यह आधारित है? भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए।

चक्रीय अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उत्पादन के रैखीय मॉडल के बजाय (टेक-मेक-यूज-थ्रो अवे) उत्पादन का पुनर्चक्रण व पुनर्प्रयोग कर अर्थव्यवस्था सृजित करने से है।

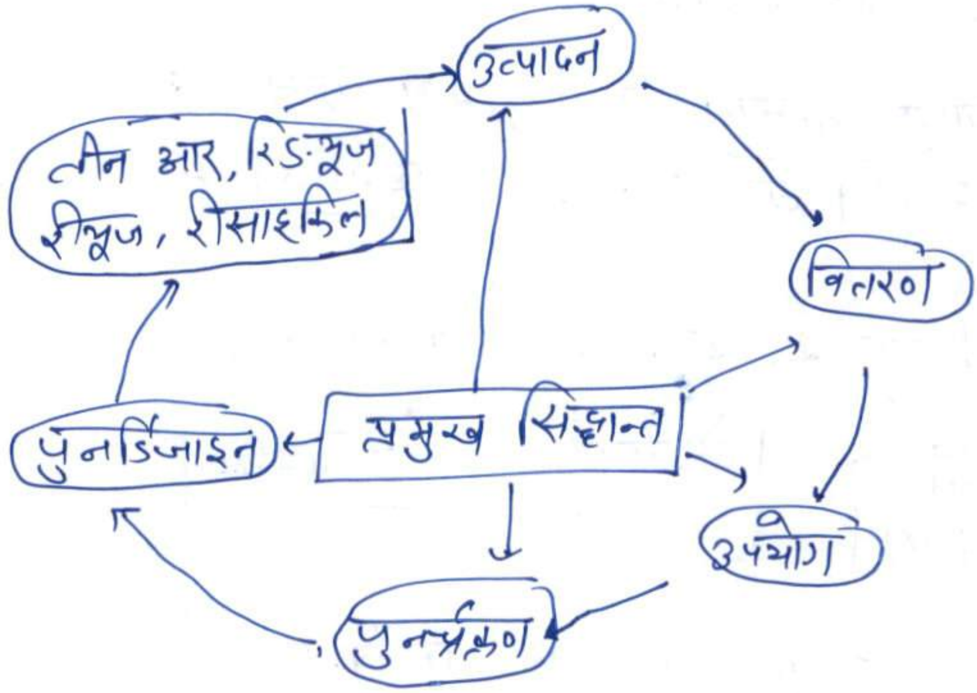
उत्पादन
तीन आर, रिड्यूज, रीयूज, रीसाइकिल
वितरण
पुनर्डिजाइन
प्रमुख सिद्धान्त
उपयोग
पुनर्चक्रण

अन्य सिद्धान्त → साझा करना।
→ पट्टे पर देना।
→ नवीन वस्तुओं का निर्माण।
→ उत्पादकों का दायित्व (EPR) जैसे सिद्धान्त।

भारत हेतु प्रासंगिकता

① बढ़ती जनसंख्या व संसाधनों की सीमितता के परिप्रेक्ष्य में।

② 'समावेशी विकास' व 'अंतर- पीढ़ीगत समता' के परिप्रेक्ष्य में

③ रोजगार सृजन - नीति आयोग के अनुसार चक्रीय व्यवस्था आगामी 4-5 वर्षों में 1.4 करोड़ रोजगार सृजन कर सकती है।

④ जलवायु परिवर्तन के हेतु कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन व INDC लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु।

⑤ अपशिष्ट की समस्या से बचने हेतु।

- ठोस कचरा
- प्लास्टिक कचरा
- ई कचरा

उपर्युक्त प्रासंगिक महत्व की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तनों - संसाधन दक्षता रणनीति, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट उपागम के साथ जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

5. Assess the performance of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana in achieving its stated objective of financial inclusion. **(150 words) 10**

वित्तीय समावेशन के अपने निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के प्रदर्शन का आकलन कीजिए।

प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 में व्यापक वित्तीय समावेशन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को मुहैया कराने के लिये शुरू की गई फ्लैगशिप योजना है जिसमें मुख्य ज़ोर बैंक खाता खोलने पर दिया जाता है।

कार्यक्रम की सफलताएँ

① खातों की संख्या :- इंडिया फाइंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 80% वयस्कों के पास बैंक खाते हैं।

② सामाजिक सुरक्षा - लगभग 13-14 % खाता-धारकों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हिस्सा लिया है।

- 'रू-पे' कार्ड धारकों हेतु 2 लाख का दुर्घटना बीमा।

③ लैंगिक समानता :- 35 करोड़ खातों में से लगभग 18 करोड़ महिलाओं के।

④ क्षेत्रीय समानता :- आधे से अधिक खाते ~~शहरी~~ व अर्द्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में

⑤ खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सरकार को 1 लाख करोड़ की बचत।

चुनौतियाँ

① व्यापक डिजीटल निरक्षरता।

② बैंकों का समावेशन व ग्रामीण पहुँच के मुद्दे।

③ विमुद्रीकरण के काले धन की समस्या।

④ ओवरड्राफ्ट सुविधा किन्तु इसके लिये धन के स्रोत की अस्पष्टता।

⑤ बैंकों की शून्य धन खातों को खोलने की अनिच्छा।

इस प्रकार प्रदर्शन के तौर पर इसे व्यापक सफल योजना माना जाता है जिसने लगभग 2/3 किसानों व गरीब जनसंख्या को औपचारिक ऋण स्रोतों से जोड़कर वित्तीय रूप से सशक्त बनाया है।

बैंक कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण व जन-जागरूकता द्वारा इसका लाभ बढ़ाया जा सकता है।

6. How does pollution in rivers impact the surrounding ecosystem? Explain why such pollution has not shown signs of improvement, despite various government initiatives. **(150 words) 10**

नदियों के प्रदूषण से आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र कैसे प्रभावित होता है? समझाइए कि विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद इस प्रकार के प्रदूषण में सुधार के संकेत क्यों नहीं हैं।

केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार देश की ५२ नदियों में कम से कम २ प्रदूषक अपनी निर्धारित सीमा से अधिक पाये गये हैं।

- नदी प्रदूषण के स्रोत
  - बिंदु स्रोत
    - औद्योगिक अपशिष्ट
    - नगरपालिका नाले।
  - गैर बिंदु
    - वर्षा बहाव
    - कृषि अपशिष्ट

प्रभाव

① स्वास्थ्य पक्ष – हैजा, पीलिया, टायफॉइड जैसी बीमारियाँ।
- नाइट्रेट - ब्लू बेबी सिन्ड्रोम।

② नहाने से चर्म रोग।

③ जैव-विविधता हानि :- विभिन्न जानवरों की जातियों का मरना।

③ जैव संचयन → पारा, यूरेनियम जैसे प्रदूषक।

④ आर्थिक हानि :- प्रदूषित जल से उत्पादकता

(मनुष्यों की) की हानि।

– मछुआरों आदि की आजीविका समाप्त होना।

विभिन्न सरकारी पहलें जैसे राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण योजना, नमामि गंगे प्रोजक्ट के बावजूद नदियाँ प्रदूषित हैं क्योंकि –

① गैर-बिंदु स्रोतों पर अंकुश लगाना कठिन है जैसे- बारिश के जल से प्रदूषक आना।

② केन्द्र-राज्य, राज्य-स्थानीय संस्थाएँ में समन्वय का अभाव है।

③ कृषि उर्वरकों की (नाइट्रोजनी) सब्सिडी नाइट्रोजन प्रदूषण को बढ़ा रही है।

④ अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव – सीधे नदियों में बहाना।

⑤ औद्योगिक बहिस्रावों पर रोक नहीं।

इन सबके अतिरिक्त जनजागरूकता व नदी के प्रति अपनेपन का अभाव प्रमुख कारण है। जलपुरुष राजेन्द्र सिंह के अनुसार लोगों को नदियों से जोड़कर व राजनीतिक इच्छाशक्ति से इसे दूर किया जा सकता है।

7. What is project MANAV launched by the Department of Biotechnology? Highlight the significance of this project. **(150 words) 10**

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरंभ की गई मानव (MANAV) परियोजना क्या है? इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालिए।

मानव परियोजना मुख्यत: डाटा के

8. Highlighting the properties and applications of superconductors, discuss the constraints related to their practical use. **(150 words) 10**

अतिचालकों के गुणों और अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए, इनके व्यावहारिक उपयोग से संबंधित बाधाओं की विवेचना कीजिए।

अतिचालकता से तात्पर्य अर्द्धचालकों के वैसे गुण से है जिसमें वे सामान्य ताप व धारा पर तो अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं किन्तु अधिक ताप पर अतिचालकों अर्थात न्यूनतम प्रतिरोध पर अत्यधिक धारा प्रवाह दक्षता प्रदर्शन, की भाँति व्यवहार करते हैं। उदा० सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि।

अनुप्रयोग

① इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का मूल आधार
   - मोबाइल विनिर्माण (सिलिकॉन वेफर का प्रयोग।
   - बैटरी प्रौद्योगिकी में।
   - कंप्यूटरों में व्यापक पैमाने पर।

② सौलर-सेल में सोलर प्लेट के निर्माण में।

③ ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में
   - न्यूनतम प्रतिरोध का गुण।

④ भविष्य की प्रौद्योगिकियों जैसे उद्योग 4.0 की व्यापक अवसंरचना हेतु।

व्यावसायिक उपयोग की बाधाएँ

① अतिचालकता का गुण निश्चित परिस्थितियों में ही उत्पन्न होता है।
- अधिक ऊर्जा की आवश्यकता।

② अर्द्धचालकों की आपूर्ति की समस्या।
- भारत में प्राकृतिक रूप से अत्यन्त कम मात्रा।

③ व्यापक अनुसंधान एवं विकास का अभाव
- कुशल पेशेवरों व वैज्ञानिकों का अभाव।
- उद्योग-अकादमी समन्वय का अभाव।

उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने हेतु व्यापक अनुसंधान को बढ़ावा देना, उद्योग-अकादमी सहयोग व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति से इसे जोड़ना आगामी कदम होना चाहिए।

9. Discuss the reasons behind India becoming a major destination as well as a transit hub for drug trafficking in South Asia. How does this effect India's internal security? **(150 words) 10**

दक्षिण एशिया में भारत के मादक पदार्थों की तस्करी के प्रमुख गंतव्य स्थल के साथ-साथ पारगमन केंद्र बनने के कारणों पर चर्चा कीजिए। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है?

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नशेबाजों की संख्या व तस्करों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

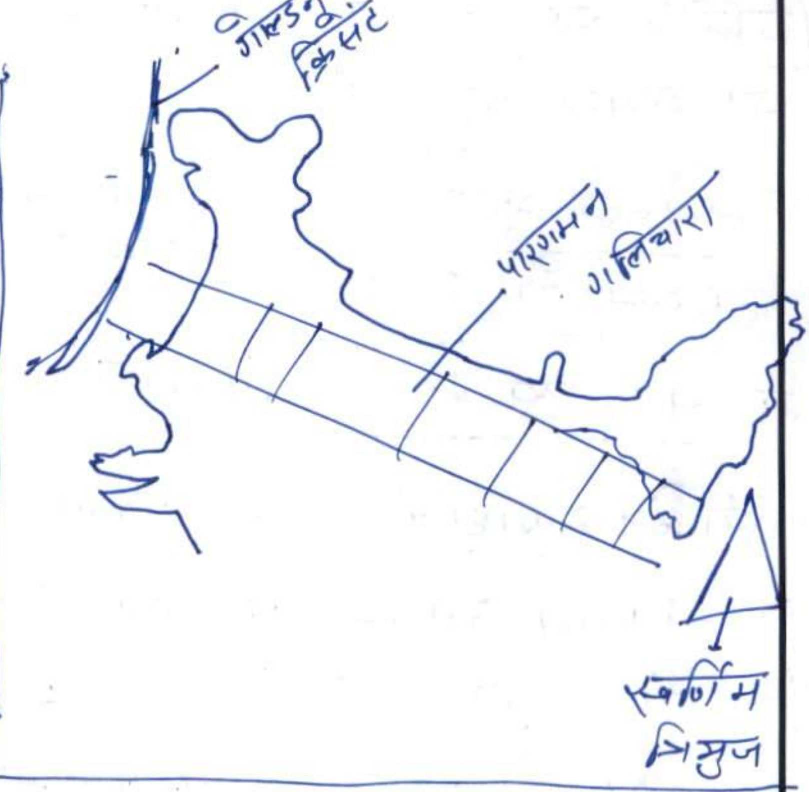

कारण

① भारत की भौगोलिक अवस्थिति।

② छिद्रित सीमाएँ।

③ केन्द्र राज्य समन्वय का अभाव। पंजाब राज्य में पाकिस्तान से तस्करी।

④ राजनेता - अफसर - अपराधी, गठजोड़।

⑤ प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यक्षमता में ~~वृद्धि~~ कमी।

⑥ अप्रभावी सीमा प्रबंधन के साथ-साथ कानूनों

में विद्यमान कमियाँ।

आंतरिक सुरक्षा प्रभाव

① अवैध वित्तीयन :- ये गतिविधियाँ उत्तर पूर्व मिलिटेंट समूहों, माओवादियों की वित्तीयन का प्रमुख स्रोत है।

② नशेबाज युवा कट्टरपंथी ताकतों के प्रति आसानी से आकर्षित होते हैं। उदा० यूरोप में आई. एस समर्थित अधिकांश नशेबाज हैं।

③ संगठित अपराध व आतंकी गठजोड़ :- दोनों का समन्वय अधिक अस्थिरता उत्पन्न करता है जैसे - दाऊद की 'डी कंपनी'।

④ अफसरों का भ्रष्टाचार सुरक्षा सुभेद्यता बढ़ाता है।

अतः चुनौती से पार पाने के लिये न केवल आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा, बल्कि बाह्य देशों - उदा० बांग्लादेश आदि से भी सहयोग करना होगा। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का पालन करना व जन जागरूकता आवश्यक है।

10. The development of border areas is an important element in border management. In this context, discuss how the Border Area Development Programme (BADP) seeks to ameliorate the problems faced in border areas. **(150 words) 10**

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास वस्तुतः सीमा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP), सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं में कैसे सुधार लाना चाहता है।

लगभग 7500 किमी. लंबी स्थल रेखा के साथ-साथ जलीय सीमा का प्रबंधन केवल सैन्य पक्षों से संभव नहीं है। इसके लिये सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास एक प्रमुख आवश्यक तत्व है।

क्यों आवश्यक

① अवसंरचना विकास से सैन्य आवाजाही में आसानी।

② स्थानीय आसूचना में वृद्धि।

③ विकेन्द्रित व बॉटम-अप विकास से राष्ट्र-वादी भावनाएँ व सैन्य ऑपरेशनों में सहयोग को बढ़ावा मिलता है

- इन्हीं कारणों से गृह मंत्रालय के अधीन सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा 2004-05 से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

प्रमुख उद्देश्य

1. सीमा के पास निश्चित दूरी तक अवसंरचना विकास।
2. सामाजिक अवसँरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य विकास करना।
3. सीमा प्रबंधन में स्थानीय लोगों का संहयोग लेना।
4. सैन्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जनजागरूकता को बढ़ाना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के लिये मंत्रालय द्वारा अनेक परियोजनाएँ पूरी की गई है -

1. व्यय में वृद्धि।
2. सड़क निर्माण।
3. स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
4. स्वास्थ्य, शिक्षा हेतु विद्यालयों, अस्पतालों का निर्माण।

अतः सीमा प्रबंधन व सुरक्षा के लिये उपर्युक्त कार्यक्रम अत्यन्त व्यापक है व भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण भी है।

11. Examine whether Fixed Term Employment will be able to achieve the objectives of ease of doing business, achieving labour welfare and job creation. **(250 words) 15**

परीक्षण कीजिए कि क्या नियत अवधि का रोजगार, ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, श्रम कल्याण और रोजगार सृजन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

हाल ही में केन्द्रीय रोजगार भर्ती नियमों में संशोधन कर नियत अवधि के रोजगार हेतु उद्योगों का दायरा बढ़ाया गया है। नियत अवधि के रोजगार अनुबंध आधारित रोजगार होते हैं जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि जैसे लाभों से छोड़कर अन्य सभी लाभ कर्मचारी को अनुबंध अवधि तक प्राप्त होते हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनैस पर प्रभाव

सकारात्मक

1. श्रम कानूनों में सरलता।
2. कंपनियाँ अधिक आयेंगी।
3. नियोक्ता पर दबाव कम होगा।
4. कंपनियों की लागत में कमी द्वारा प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि।
5. रेगुलेटरी कॉलेस्ट्रॉल (आर्थिक समीक्षा 2017-18) से निजात पाने में मदद।

चुनौतियां :

- समवर्ती सूची का विषय होने से राज्यों की मंजूरी आवश्यक।
- राज्यवार भिन्नता का होना।

श्रम कल्याण व रोजगार सृजन

सकारात्मक पक्ष

① मौसमी बेरोजगारी से निजात।
② निश्चित समय तक स्थायी रोजगार।
③ कंपनियों के विभिन्न भत्तों जैसे लाभों को पाने के हकदार।
④ श्रम कानूनों में लचीलापन लाकर अल्पकालिक बेरोजगारी से लड़ना।

चुनौतियां

→ कंपनियों का ~~की~~ कर्मचारियों पर दबाव बढ़ सकता है।
- बेरोजगारी की मुख्य समस्या को हल नहीं करता है।
→ लगातार अनुबंध नवीनीकरण करते रहना व स्थायी न करना सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत है।

→ सुभेद्यता में वृद्धि हो सकती है।

→ दीर्घकालिक समाधान नहीं।

अतः अर्थव्यवस्था में मंदी व व्यापक बेरोजगारी को देखते हुए श्रम गहन उद्योगों व निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से रोजगार संवर्धन व नियोक्ता प्रोत्साहन की दृष्टि से यह कदम उचित है किन्तु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये।

- श्रम सुधारों को लागू करना चाहिये।
- अनुबंध में वस्तुनिष्ठ आधारों को शामिल करना।
- निश्चित समयोपरांत स्थायी नियुक्ति का आदेश जारी करना। आदि।

अतः उपर्युक्त प्रावधानों से निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को गति देकर रोजगार संवर्धन किया जा सकता है।

12. A growing livestock sector augurs well for the low income households to augment their income and escape poverty. Discuss. Further, suggest some strategies for ensuring sustainable livestock sector growth in India. **(250 words) 15**

एक वृद्धिशील पशुधन क्षेत्रक निम्न आय वाले परिवारों के लिए अपनी आय में वृद्धि करने और गरीबी से बाहर निकलने हेतु शुभ संकेत है। चर्चा कीजिए। इसके अतिरिक्त, भारत में पशुधन क्षेत्रक का संधारणीय विकास सुनिश्चित करने हेतु कुछ रणनीतियों का सुझाव दीजिए।

भारत एक कृषि प्रधान देश के साथ पशु-प्रधान देश भी है। भारत में विश्व के सर्वाधिक पशु पाये जाते हैं। (17 करोड़ से अधिक)।

पशुधन क्षेत्रक का आजीविका संवर्धन में महत्व

① अतिरिक्त आय सृजन
- दूध विक्रय।
- खाद निर्माण।
- दूध-उत्पादों का निर्माण।
- मुर्गियों का अंडा उत्पादन।
- मांस विक्रय।

② एकीकृत फार्मिंग प्रणाली में सहायक।

कृषि
- बैलों का प्रयोग जुताई में।
- खाद का प्रयोग फसल क्षमता वृद्धि हेतु।

③ स्वास्थ्य पक्ष को मजबूत कर उत्पादकता वृद्धि में :-

- दूध में विद्यमान विटामिन (ADEK)

- मुर्गियों के अंडों में पोषक तत्वों की मौजूदगी
- हिडेन हंगर (Hidden Hunger) से लड़ने में मदद।

④ जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य :-

- चारा फसलों हेतु कम पानी की जरूरत।

⑤ लागत प्रभावी पद्धति।

⑥ व्यापार भी किया जा सकता है।

संधारणीय विकास की प्रमुख रणनीतियाँ।

① अनुसंधान व विकास -

→ पशुधन नस्ल सुधार।
→ वीर्य ~~तस~~ संरक्षण।
- क्रॉस-ब्रीडिंग को मजबूत बनाना।

② देशी नस्लों पर बल देना

→ देश की जलवायु के अनुकूल।
→ चारे -पानी की कमी के प्रति अधिक प्रतिरोधी।
→ उत्पादों में पोषक तत्वों का आधिक्य।

③ बाजारों का विकास करना :-

- APMC के उत्तराधिकार को समाप्त करना

- ग्रामस (GrAMS) की स्थापना करना।
- ई- बाजारों को प्रोत्साहन ।

④ पशु-मेलों का आयोजन करते रहना ।

⑤ पशु चिकित्सा पर बल देना
  - पशु UID, नकुल स्वास्थ्य पत्र आदि पर बल देना।

⑥ पशुधन क्षेत्र में परिवार पक्ष -
  - सहकारिता को प्रोत्साहन ।
  - जागरूकता बढ़ाना ।
  - वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल देना ।

हालिया समय में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, रा० डेयरी प्रजनन एवं अनुसंधान कार्यक्रम जैसे मिशनों के साथ तकनीक का प्रयोग कर अक्षरशः क्रियान्वयन कर इजराइल जैसे देशों से सीख लेकर पशुधन को ग्रामीण विकास के इंजन के रूप में स्थापित किया जा सकता है

13. Examine whether the time has come for India to usher in full liberalisation of the Capital Account. **(250 words) 15**

परीक्षण कीजिए कि क्या भारत के लिए पूंजी खाते के पूर्ण उदारीकरण की शुरुआत करने का समय आ गया है।

पूंजी खाते के उदारीकरण से तात्पर्य देश के भुगतान संतुलन खाते के पूंजी पक्ष में आये निवेश की मुद्रा को किसी विदेशी मुद्रा में पूर्णतः परिवर्तनीय बनाना।

उदा० एफ. आई. आई. निवेश आदि।

उदारीकरण के लाभ

① भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक विदेशी पूंजी अंतर्वाह का आना।

② भारतीय मुद्रा र में मजबूती।

③ चालू खाते खाते के अनुपूरण में सहायता।

④ अधिक विदेशी निवेश -
  - प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाता है।
  - प्रबंधन व संचालन क्षमताओं में वृद्धि करते हैं।
  - निर्यात क्षमता में वृद्धि करते हैं

⑤ अन्य देशों में प्रयुक्त - पश्चिमी देश व उ०प द० पू० एशिया के देश।

हाल ही में RBI के वरिष्ठ सदस्य ने भी इसकी वकालत की है।

नकारात्मक पक्ष

① अस्थिरता में वृद्धि :- इसी वर्ष आर्थिक समीक्षा के अनुसार एफ.आई.आई (FII) नकारात्मक रहा है।

② वैश्विक संकटों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि
उदा० अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि।

③ 1997 का एशियन टाइगर्स की अर्थव्यवस्था संकट जैसे उदाहरण।

④ डच डिजीज प्रभाव :- आधिक्य पूंजी का गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में नियोजन जैसे- रियल इस्टेट, जबकि बाहरी देयताओं में निरंतर वृद्धि होगी।

⑤ एकदम से पूंजी बाहर जाने पर अर्थव्यवस्था को संभालने में कठिनाई।

अतः उपर्युक्त तर्कों से विवेचन करने पर अन्ततः 'एस. तारापोर समिति' की कसौटियों का विवेचन करना आवश्यक होगा। -

- → राजकोषीय स्थिरता
- → गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ (6% से कम हों)
- → समष्टि अर्थ-शास्त्रीय स्थिरता।
- → मुद्रास्फीति नियंत्रण।

चूंकि भारत NPA के मानदंड को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों पर खरा उतरता है अतः प्रभावी बैंकिंग सुदृढ़ीकरण, निर्यातों की दृढ़ता (Robustness) बढ़ाकर एवं व्यापक अर्थशास्त्रीय स्थिरता में इसे लागू करना चाहिए।

14. Highlighting the challenges to agriculture extension in India, discuss how ICT can help in addressing them. **(250 words) 15**

भारत में कृषि विस्तार के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, चर्चा कीजिए कि इन्हें दूर करने में ICT से कैसे सहायता मिल सकती है।

कृषि विस्तार से तात्पर्य उन सेवाओं से है जिनके द्वारा किसानों को कृषि के विभिन्न साधनों, पद्धतियों, अनुप्रयोगों व तकनीकों के संबंध में जागरूक बनाया जाता है।

भारत में इसकी शुरुआत 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से मानी जाती है।

कृषि विस्तार में प्रमुख चुनौतियाँ

① व्यापक अवसंरचना का अभाव :- भारत में कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVK) की उपस्थिति संख्या व मात्रा दोनों स्तरों पर कम है।

② भाषा का मुद्दा :- अंग्रेजी या हिन्दी में प्रयोग होना।

③ कर्मचारियों में संवेदनशीलता का अभाव।

④ विस्तार सेवा कर्मचारियों के व्यापक

प्रशिक्षण का अभाव।

⑤ कर्मचारियों की कमी।

⑥ नई तकनीकों को किसानों को समझने में कठिनाई।

⑦ किसान पक्ष में प्रमुख है कि कृषि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण किसान के पास सूचना सेवाओं को प्राप्त करने का समय नहीं होता।

→ सूचनाओं के महत्व के बारे में जागरूकता का अभाव।

आई. सी. टी. की भूमिका

① समावेशी। — हर किसान तक सेवा। फसल के हर चरण की जानकारी। उदा॰ कर्नाटक का मौसम पूर्वानुमान जानकारी मॉडल।

② टू-वे (Two-way approach)

③ ऑडियो - विजुअल में उपलब्ध।

④ 24×7 (हर समय उपलब्ध)

⑤ स्थानीय भाषा में रूपान्तरण किया जा सकता है।

⑥ प्रायोगिक क्रियाओं का दूरस्थ प्रदर्शन भी वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुँचाया जा सकता है।

⑦ अन्य सेवाएँ :- मौसम पूर्वानुमान, बीमा, सिंचाई आदि।

हालांकि उपर्युक्त महत्व के बाद भी डिजीटल निरक्षरता, अवसंरचना की कमी, भाषायी मुद्दे विद्यमान हो सकते हैं, जिन्हें हल किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त सन्दर्भ में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान' को 'एम - किसान' पोर्टल से जोड़कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही आई.टी.सी. (ITC) के ई चौपाल, मध्यप्रदेश के ज्ञानदूत जैसे मॉडलों से सीख प्राप्त की जानी चाहिये।

15. Now that it has been two years since introduction of GST in India, do you think the system is on the path to achieve its intended objectives? Support your answer with relevant facts. **(250 words) 15**

अब जबकि भारत में GST को लागू हुए दो वर्ष हो गए हैं, क्या आप मानते हैं कि यह प्रणाली अपने अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है? प्रासंगिक तथ्यों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

वस्तु एवं सेवा एक गंतव्य आधारित, उपभोग आधारित अप्रत्यक्ष कर है।

भारत में जी. एस. टी. लागू करने के लाभ

① कर अनुपालन में वृद्धि

- अप्रत्यक्ष कर दाताओं में 65 % से अधिक वृद्धि हुई है।
- डिजीटल अवसंरचना से कर परिहार करना मुश्किल हो गया है।
- 'सेल्फ पुलिसिंग तंत्र' से इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु प्रोत्साहन मिलता है।
- जी. एस. टी. कंपोजिशन योजना का प्रभाव। (1-6 %. की दर पर बिना बोझिल प्रक्रिया के कर देना)

② प्रत्यक्ष कर अनुपालन में भी वृद्धि :- पिछले 4 वर्षों में प्रत्यक्ष कर रिटर्न भरने वालों

की संख्या में 80% की वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण जी.एस.टी. डेटा को माना जाता है।

② कर अधिकारियों की निरंकुशता में कमी- पूर्ण प्रणाली डिजीटलीकृत है।

③ राज्यों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहन :- संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुरूप ई-वे बिल जैसे तंत्र ने राज्य करों, शुल्कों की मात्रा में कमी कर व्यापर प्रोत्साहित किया है।

④ वेयर हाउस-ऑक्शेसन व करों की मात्रा में कमी :- हर राज्य में समान कर संरचना से अनैतिक व्यापार। संचालनों में कमी।

⑤ कर-जी.डी.पी. अनुपात में वृद्धि -
- सेवा कर में वृद्धि।

उपर्युक्त लाभों के बावजूद प्रमुख उद्देश्यों जैसे - एक देश : एक कर, कर अनुपालन में सहूलियत, सभी प्रत्यक्ष करों का समामेलन जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति

निम्न कारणों से बाधित हुई है -

① मदों का बाहर रहना - पैट्रोल, तंबाकु, एविएशन टरबाइन फ्यूल, शराब आदि। (प्रमुख राजस्व में 40% से अधिक योगदान राज्यों को)

② विभिन्न कर दरें :- 0.5, 12, 18, 28 आदि।

③ जी.एस. टी नेटवर्क में समस्या - निजी हाथों में, ~~बि~~ ~~असे~~ डाटा चोरी का मुद्दा। - वेबसाइट हैक होना।

④ ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में सेस व सरचार्ज की अनुपस्थिति कर सरलीकरण के साथ इन उद्योगों की वृद्धि को प्रभावित करती है

इस प्रकार उपर्युक्त चुनौतियों से लड़कर ही सहकारी संघवाद के प्रमुख उपकरण के रूप में जी. एस. टी. को स्थापित कर भारत में कर संरचना को पूर्णतः सरलीकृत किया जा सकता है

16. Write a brief note on Carbon Capture and Storage. Mention its potential benefits and discuss the challenges that need to be addressed for its wide-scale deployment in India. **(250 words) 15**

कार्बन अभिग्रहण और भण्डारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके संभावित लाभों का उल्लेख कीजिए तथा भारत में इसके व्यापक पैमाने पर परिनियोजन में आने वाली उन चुनौतियों की विवेचना कीजिए जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है।

कार्बन अभिग्रहण एवं भंडारण से तात्पर्य जलवायु परिवर्तन रोकने की 'शमन' प्रविधि से है जिसके अन्तर्गत कारखानों से निकलने वाले कार्बन की मात्रा को अभिग्रहित कर उसके सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है।

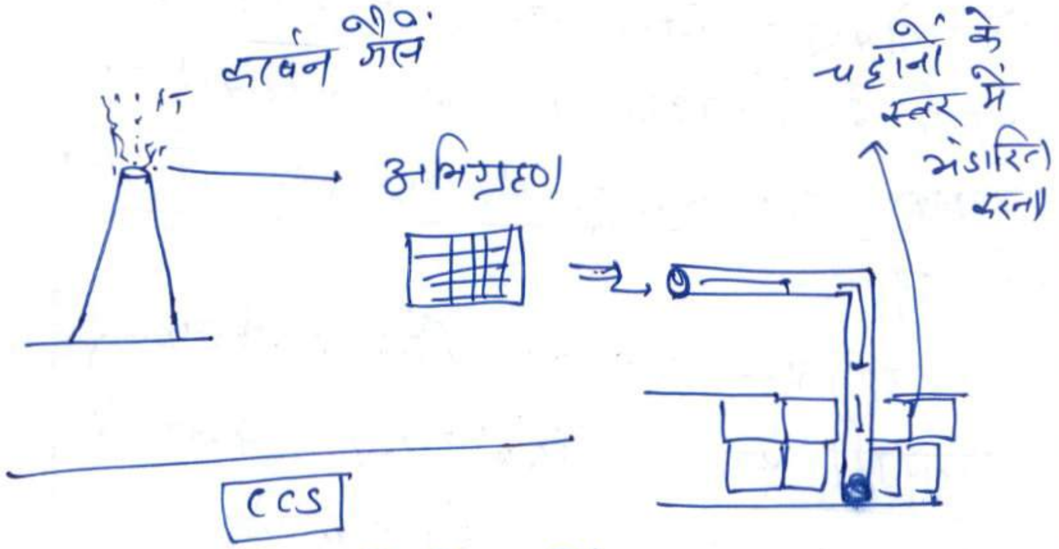

CCS

यह दो प्रकार से होता है

① प्राकृतिक रूप से - पेड़ों व हवा में
- आर्द्रभूमियों में

② कृत्रिम रूप से :- उपर्युक्त चित्र के माध्यम से।

लाभ

① जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार
शमन प्रौद्योगिकी का प्रमुख अंग।

② INDC लक्ष्यों को पूरा करने में।

③ भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने में –
- बायोचार के माध्यम से।

④ कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
– मृदा में भंडारित कार्बनिक पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण होता है।

⑤ तेल व गैसों के निष्कर्षण में – कार्बन की पम्पिंग द्वारा कार्बन प्रविष्ट कराकर तेल व गैस निकाला जाता है।

⑥ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाव हेतु।

⑦ अपेक्षाकृत सस्ती तकनीक।

चुनौतियाँ

① तकनीकी पक्ष – इन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की तकनीकें अभी व्यापक मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।
उदा० डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग।

② कुप्रभावों की अनभिज्ञता :- समुद्र में चूने को मिलाना, लौह तत्व मिलाकर फाइटो-प्लैंकटन की संख्या बढ़ाना जैसे उपायों का दीर्घकालिक कुप्रभाव ज्ञात नहीं है।

③ चट्टानों में संग्रहण में लीकेज न होने की गारंटी नहीं।

④ समुद्री भंडारण - समुद्री जैव विविधता पर प्रभाव
- महासागरीय अम्लीकरण।

उपर्युक्त चुनौतियों के सन्दर्भ में यही कहा जा सकता है कि प्राकृतिक सिंकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये व कृत्रिम भंडारण को उपयुक्त परीक्षणों के बाद ही लागू किया जाना चाहिये।

17. Highlight the gender specific challenges faced during disaster management. In this regard, discuss how the disaster management cycle can be made more gender sensitive. **(250 words) 15**

आपदा प्रबंधन के दौरान सामने आने वाली लैंगिक विशिष्ट चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इस संबंध में, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार आपदा प्रबंधन चक्र को लैंगिक रूप से और अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन से तात्पर्य आपदा आने से पूर्व, आपदा के समय व आपदा पश्चात की जाने वाली वृहद, विशिष्ट व एकीकृत कार्यवाही से है ताकि आपदा की पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान कार्यों व आपदा पश्चात व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके।

लैंगिक विशिष्ट चुनौतियाँ

① महिला संबंधी अपराधों की सुभेद्यता : कुछ वर्षों पहले बिहार की बाढ़ के समय सिंदूर की मांग में वृद्धि हुई क्योंकि इसे लगाने से महिलाओं के प्रति शारीरिक अपराधों में कमी हुई थी।

② पुरुष विशिष्ट प्रवास :- इसके कारण आपदाओं का दुष्प्रभाव उद्गम क्षेत्र की महिलाओं पर पड़ता है।

परिवार, बाहरी काम व आपदा का

तिहरा बोझ।

③ महिलाओं की निरक्षरता व जागरूकता में कमी।

④ आपदा अनुकूलन नीतियों के प्रति शिक्षा की कमी।

⑤ महिलाओं के पास भू-स्वामित्व अधिकार न होने से फसल-बीमा जैसे आपदा रक्षोपायों का प्रयोग न कर पाना।

⑥ सौदेबाजी क्षमता कम होने के कारण बलात. प्रवासन व पुनर्वास का अभाव।

आपदा प्रबंधन चक्र को लैंगिक रूप से अधिक संवेदनशील बनाने के उपाय

① तैयारी चरण
- महिलाओं को प्रशिक्षित करना।
- आपदाओं की जानकारी देना।

② मिटिगेशन चरण :-
- प्राथमिकता में महिलाओं व बच्चों को रखना।

③ आपदा - दौरान चरण :-

- अधिकारियों को महिला संवेदनशील प्रशिक्षण देना।
- महिला विशिष्ट बजट निर्माण करना।

④ आपदा पश्चात चरण :-

- पुनर्वास में प्राथमिकता प्रदान करना
- आपदा बल में महिला कर्मचारियों को भर्ती करना।
- प्रभावी चिकित्सा व खाद्यापूर्ति उपलब्ध कराना।

अतः उपर्युक्त चरणात्मक उपायों के साथ प्रशासन - स्थानीय व्यापक भागीदारी के सेंडाई फ्रेमवर्क मॉडल की पालना करते हुए कानूनी पक्षों पर भी बल दिया जाये ताकि 'महिला विशिष्ट बटालियन' का निर्माण हो। साथ ही आपदा दौरान महिला अपराध नियंत्रण पर बल प्रदान किया जाये।

18. Though there are some notable individual achievements, the overall participation of women in scientific research has been abysmally low. Examine. What steps have been taken by the government in this regard? **(250 words) 15**

भले ही, कुछ उल्लेखनीय व्यक्तिगत उपलब्धियाँ हों, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में महिलाओं की समग्र भागीदारी अत्यंत निम्नस्तरीय रही है। परीक्षण कीजिए। इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारत में महिला वैज्ञानिकों का ज़िक्र करते ही टेसी थॉमस जैसे अत्यन्त कम नाम ही मस्तिष्क में आते हैं। इस बात के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं -

① भारत में विज्ञान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 100 में से केवल 15 महिलाएँ हैं। जबकि विश्व में 30 हैं।

② शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (1958 में स्थापित) में विगत 61 वर्षों में केवल 20 पुरस्कार महिलाओं को मिले हैं।

प्रवृत्ति के कारण

① सामाजिक कारण

→ सामाजिक बंदिशें
→ पितृसत्तात्मक समाज
→ क्षमता पर अविश्वास।

② आर्थिक कारण
- वेतन में अंतराल।
- शिक्षा तक पहुँच में कमी के कारण रोजगार में कमी।

③ अन्य - विवाह आदि के कारण विस्थापित हो जाना।

सरकारी कदम

① महिला वैज्ञानिक योजना :- विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 27-57 वर्ष की महिलाओं को वापिस अनुसंधान के क्षेत्र में जोड़ने हेतु।

② किरण (Knowledge involvement through Research Advancement & Nurturing)

अम्ब्रेला योजना
- महिला प्रौद्योगिकी पार्क योजना
- क्यूरी योजना (विश्वविद्यालयों में महिलाओं हेतु नवाचार संवर्धन)
- महिला मोबिलिटी योजना - विवाहित महिलाओं को वापिस जोड़ने हेतु।

③ भारत - यू. एस. महिला फेलोशिप योजना।

④ जैव- प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में ~~म~~ महिला प्रोत्साहन को प्रभावी बनाने के लिये बायो केयर (Career Advancement through Re parting) योजना।

उपर्युक्त सरकारी प्रयासों के अलावा व्यापक जनजागरूकता व महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। इसके लिये 'मिशन मंगल' जैसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि भारत SDG-5 के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

19. Discuss the significance of the recent amendments made in the NIA act and the UAPA Act for countering terrorism. **(250 words) 15**

आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु NIA अधिनियम और UAPA अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों के महत्व की विवेचना कीजिए।

विश्वमें आतंकवाद व इसकी रणनीतियों की बढ़ती प्रवृति, बदलती रणनीतियाँ, आतंकवाद का बहुआयामी होना आदि को रोकने के लिये प्रभावी कानूनी व संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। हालिया कानूनी संशोधन इसी बात की पुष्टि करते हैं।

यू.ए.पी.ए. में संशोधन

① कानून का विस्तार :- संगठनों के साथ-साथ व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करना।

② स्वीकृति :- जाँच करने के लिये राज्य के डी.जी. के बजाय NIA के डी.जी. की स्वीकृति को लागू करना।

③ जाँच के लिये पुलिस अधीक्षक रैंक के बजाय इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को अधिकृत करना।

④ अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों जैसे - आतंकी वित्तीयन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

से कानून को सुसंगत बनाना |

एन. आई. ए. में संशोधन

① कानूनी दायरे में वृद्धि :- साइबर क्राइम जैसे अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों का समावेशन |

② जाँच शक्तियों में वृद्धि :- विदेशों में जाँच की शक्तियाँ देना |

③ मुकदमे न्याय में तीव्रता :- फास्ट ट्रैक कोर्ट व 'सेशन कोर्ट' को NIA कोर्ट में तब्दील करने का प्रावधान |

महत्व

① भारतीय आंतरिक सुरक्षा खतरे -
- पाकिस्तान राज्य समर्थित आतंकवाद |
- हालिया पुलवामा हमला |
- आपराधिक संगठन - आतंकी गठजोड़ |

② अपराधों की बहुआयामी प्रवृत्ति :- उदाहरण के लिए पहले NIA को आतंकी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति को 'आर्म्स एक्ट' के तहत

गिरफ्तार करने की शक्तियाँ नहीं थी।

③ व्यापक छिद्रित सीमा के प्रति भारत की सुभेद्यता।

④ ~~अ~~ मसूद अजहर को आतंकी नामित करना हो या 26/11 के आरोपी डेविड कॉलमेन का भारत प्रत्यर्पण न होना – सभी में कानूनी कमजोर पक्ष जिम्मेदार थे।

⑤ एजेंसियों व कानूनों की शक्तियाँ बढ़ाकर आतंकवाद व संबंधित अपराधों से लड़ा जा सकता है उदा० मानव तस्करी।

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों संशोधन भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हालांकि दुरुपयोग रोकने के लिये संस्थागत ~~संपूर्ण~~ मजबूती भी आवश्यक है।

20. The national security architecture needs to be robust enough to deal with present and evolving threats. Elaborating on the statement, discuss the recent steps taken for modernisation of the national security architecture.
(250 words) 15

वर्तमान और भावी (उभरते) खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को पर्याप्त सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन का सविस्तार वर्णन करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना के आधुनिकीकरण हेतु हाल ही में उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

भारत की सुरक्षा संरचना

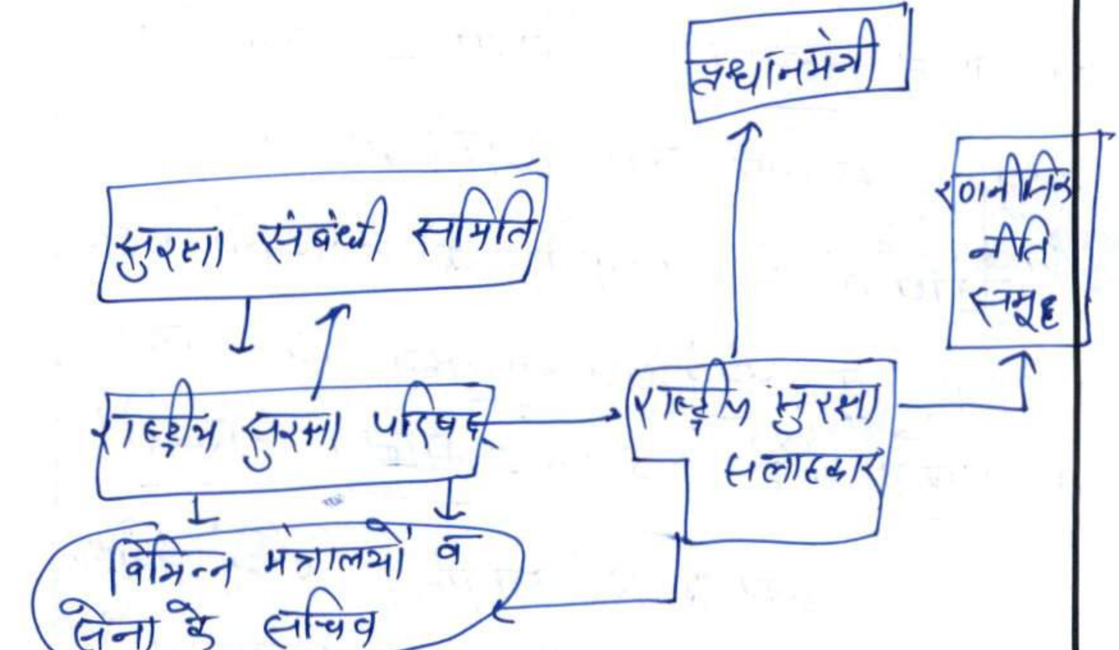
प्रधानमंत्री
रणनीतिक नीति समूह
सुरक्षा संबंधी समिति
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
विभिन्न मंत्रालयों व सेना के सचिव

भारतीय उपर्युक्त सुरक्षा संरचना के परिप्रेक्ष्य में निम्न चुनौतियाँ है -

① कार्यों का अतिव्यापन

उदा० सुरक्षा संबंधी समिति व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद-

② बैठकों का आयोजन न होना

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नियमित बैठकें आयोजित नहीं की जाती है।

③ निर्णयों में देरी :- चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ, थियेटर कमांड निर्माण, एकीकृत बैटल ग्रुप का निर्माण जैसे निर्णय अत्यन्त देरी से लिये गये हैं।

④ रक्षा विशेषज्ञों की कमी का मौजूद होना।

⑤ विभिन्न मंत्रालयों (रक्षा व वित्त) के मध्य समन्वय का अभाव।

हालिया उपाय

① राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद को पुनः सरंचित करना।

② चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (CDS) के सृजन की घोषणा।

③ रक्षा योजना समिति (DPC) का गठन

NSA ← विभिन्न मंत्रालयों के सचिव।

- रक्षा योजनाओं में तीव्रता लाने के लिये।

(4) इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स व थियेटर कमांड के गठन करने की योजना

(5) रणनीतिक नीति समूह को अधिक समावेशी बनाना व नीतियों के निर्माण में पारदर्शित लाना।

अतः चीन-पाक के दोहरे खतरे, आतंकवाद आदि से निपटने के लिये; कोल्ड स्टार्ट सिद्धान्त के अनुरूप दक्ष व त्वरित कार्यवाही के लिये सुरक्षा संरचना में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है।